इसकी, अब साढ़े पांच साल हो गये हैं तो निश्चित ही बढ़ेगा और आपने कहा कि नहीं बढ़ेगा । तो जरा इसका कारण बताने की कृपा करें । दूसरा, मान्यवर यह कि आपकी कृपा से, आपकी कोशिश से प्रदेश के हित में, तीनों प्रदेशों के हित में इस योजना को जल्दी से जल्दी कब तक कार्यान्वित कराने का आप प्रयास करेंगे ।.. (व्यवधान)... मान्यवर, यह मेरा प्रश्न मंत्री जी ने नहीं सुना क्योंकि प्रधानमंत्री जी से बात कर रहे थे । पहला तो कोस्ट-एसक्लेशन पर बता दीजियेगा और दूसरा, तीनों स्टेटस के हित में कब तक जल्दी से जल्दी इस योजना को आप स्वीकृति प्रदान करने, कराने का प्रयास करेंगे और इसको चालू करने की कोशिश करेंगे ?

श्री बी० शंकरानन्द : यह तीनों स्टेटस के हित में है कि तीनों एग्री करें और तीनों के एग्री किये बिना... (व्यवधान)...

श्री वीरेन्द्र वर्मा : आप कराने की कोशिश करें ?

श्री बी० शंकरानन्द : हम कोशिश कर रहे हैं ।

श्री वीरेन्द्र वर्मा : कब तक ?

SHRI RAJIV GANDHI: Sir, it was partly linked with the Punjab Accord. We have found it very difficult since the new, well, not new but the current Chief Minister of Haryana, rejected the Punjab Accord. We have not been able to move ahead. We would look forward to getting some specific suggestion on what he feels as a solution to the problem.

श्री वीरेन्द्र वर्मा : मान्यवर, प्रधानमंत्री जी से संबंधित है, यह 20 जून, 1987 को वर्तमान मुख्यमंत्री आये हैं और आपका जो एकोर्ड हुआ था, वह 24 जुलाई, 1985 को हुआ, जिसके अनुसार 15 अगस्त, 1986 तक यह कंपलीट हो जानी चाहिये थी यानी एक साल पहले कंपलीट हो जानी चाहिये थी अब जरा बतायें कहां मुख्यमंत्री बीच में पिक्चर में आते हैं ? वह तो आप के एकोर्ड के लागू होने के एक वर्ष बाद आये हैं ।

श्री राम अवधेश सिंह : प्रधानमंत्री जी, इस पर बोलिये न ?

श्री सभापति : पंजाब-सिचुएशन बताया न ।

श्री राम अवधेश सिंह : नहीं गलत जवाब दिया है ।

श्री राजीव गांधी : एस वाई०एल० जब बन रही थी,अभी भी बन रही है, लेकिन एस०वाई०एल० का जो बेसिस था, वह पंजाब एकोर्ड में था । जैसे ही हरियाणा के मुख्यमंत्री जी ने उसे रिजेक्ट कर दिया, अब बड़ी मुश्किल है उस बेसिस को लागू करने के लिये । तो मैं चाहूगा कि हरियाणा के मुख्यमंत्री जी एक आल्टरनेटिव प्रपोजल हमारे सामने रखें, पंजाब की सरकार के सामने रखें और फिर हम उसे देख सकेंगे ।

श्री सभापति : प्रश्न काल समाप्त ।

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

Privatisation of T.V. glass shell project at Taloja in Maharashtra

*125. SHRI B. SATYANARAYAN REDDY:
SHRI RAM CHANDRA VIKAL:

Will the Minister of DEFENCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a proposal to privatise the T.V. glass shell project at Taloja in Maharashtra established by the Bharat Electronics Ltd. (BEL) is being considered by the Central Government;

(b) whether BEL is under pressure to turn the glass shell plant into joint venture while retaining a minority share, alongwith a private party and a foreign company; and

(c) if so, what are the details of the proposal and the need for such a move for privatisation?

THE MINISTER OF DEFENCE (SHRI K. C. PANT): (a) and (b) A Memorandum of Understanding signed between BEL, Corning Glass Works, USA and Samtel India for bringing the Taloja project under a joint venture with these companies as partners, is under consideration of Government.

(c) The proposal is being considered in the context of the future growth strategies of BEL with the need to concentrate its managerial, financial and technical resources in areas of high technology and professional electronics for defence purposes. It would not be in the public interest to disclose the details at this juncture.

Pact with Bangladesh on Tinbighas

*126. SHRI MUKHTIAR SINGH MALIK:
SHRIMATI RENUKA CHOWDHURY:

Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether Government propose to scrap Indira-Mujib Pact on Tinbighas; and

(b) if not, what are the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI K. NATWAR SINGH): (a) No, Sir.

(b) The Indo-Bangladesh Land Boundary Agreement of 1974 meets both India's and Bangladesh's concerns on matters relating to the boundary and to withdraw from it would amount to reneging on an international treaty commitment.

Dam over Barak river of Assam

*127. SHRI KAMAL MORARKA: Will the Minister of WATER RESOURCES be pleased to state:

(a) whether any techno-economic study has been conducted for the construction of a dam over Barak river in Assam;

(b) if so, what are the details thereof; and

(c) by when a final decision is likely to be taken in this regard?

THE MINISTER OF LAW AND JUSTICE AND THE MINISTER OF WATER RESOURCES (SHRI B. SHANKARANAND): (a) and (b) The study covers a 161 Meters high rock-fill dam with 1500 Mega Watt installed capacity at estimated cost of Rs. 1078 crores (1983 prices). The dam will provide other benefits like flood moderation, irrigation and pisciculture.

(c) Final decision will depend on the result of the techno-economic study.

निर्वाचन-आयोग एक बहुसदस्यीय संस्था

*128. **श्री राम जेठमलानी :**
श्री राम नरेश यादव :

क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्वाचन-आयोग को बहुसदस्यीय संस्था बनाने के लिये कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव को अभी तक क्रियान्वित न करने के क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार इस संबंध में भविष्य में कोई ठोस कदम उठायेगी ; यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

विधि और न्याय मंत्री तथा जल-संसाधन मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) इस प्रस्ताव पर अभी तक कोई विनिश्चय नहीं किया गया है।